(b) if so, how do they compare with those in the developed countries;

(c) the measures proposed for modernisation; and

(d) by when the modernisation programme will be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) Modernisation of rescue services in coal mines, undertaken in accordance with the modernisation plan drawn up in this regard, is expected to be completed by the end of 1998. The plan envisaging construction of new rescue stations and rescue rooms in different coalfields, provision of state-of-the-art rescue apparatus and equipment and also upgradation of the training standards for rescue brigades etc., compares favourably with those provided in the developed countries.

लघु उद्योग क्षेत्र में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि किया जाना

780. **श्री राम जेठमलानी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार लघु औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश की वर्तमान अधिकतम सीमा कितनी है और सरकार ने इसे किस सीमा तक बढ़ाना निर्धारित किया है;

(ग) क्या सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में उल्लिखित मदों की वर्तमान संख्या को कम करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्माण के लिए आरक्षित मद-सूची से बाहर किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) इस समय लघु उद्योग एकक के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा 60 लाख रु० है। अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों/निर्यातोन्मुख लघु उद्योग एककों के लिए यह सीमा 75 लाख रु० है। सरकार, वर्तमान पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है।

(ग) से (ङ) इस समय, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की संख्या 836 है। लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

देश में बेरोजगारी

781. **श्री रामजीलाल:**
श्री जगन्नाथ सिंह:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुशल और अकुशल शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं; और

(ख) इस बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है और वह सभी बेरोजगार व्यक्तियों को कब तक रोजगार उपलब्ध करा देगी?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) 31.12.1989 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुशल/अर्धकुशल एवं अकुशल रोजगार चाहने वाले यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हो, की संख्या क्रमशः 11.8 लाख तथा 49.3 लाख थी।

(ख) यद्यपि नई आर्थिक नीति के 1991 के प्रारम्भ से रोजगार चाहने वालों की संख्या में कोई दीर्घकालिक वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी है। सरकार ने रोजगार सृजन को अपनी विकास योजनाओं हेतु किये जाने वाले प्रयासों के केन्द्र में रखा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों तथा सब-सैक्टरों यथा, कृषि, कृषि तथा ग्राम्य उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक तथा सेवा क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, पहले से चालू योजनाओं, यथा, आई आर डी पी, जे आर वाई तथा एन आर वाई के साथ-साथ नई रोजगार सृजन योजनाएं यथा, रोजगार आश्वासन योजना (इ ए एस), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर